VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (4511)

निर्धारित समय: तीन घंटे
Time Allowed: **Three Hours**

अधिकतम अंक: **250**
Maximum Marks: ***250***

सामान्य अनुदेश

इस प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका में 55+1 पृष्ठ हैं। प्रश्न-पत्र, क्यू.सी.ए. पुस्तिका के अंत में संलग्न है, जो अलग (वियोज्य) किया जा सकता है और उम्मीदवार परीक्षा के उपरांत अपने साथ ले जा सकते हैं।

रफ कार्य के लिए, इस पुस्तिका के अंत में खाली पृष्ठ दिया गया है।

पुस्तिका प्राप्त होने पर, कृपया यह जांच कर लें कि इस क्यू.सी.ए. पुस्तिका में कोई कमी न हो, फटा हुआ पृष्ठ न हो अथवा कोई पृष्ठ गायब न हो इत्यादि। यदि ऐसा हो, तो इसके बदले नई क्यू.सी.ए. पुस्तिका प्राप्त कर लें।

General Instructions

This Question-Cum-Answer (QCA) Booklet contains 55+1 pages. Question Paper in detachable form is available at the end of the QCA Booklet which can be taken away by the candidate after examination.

For rough work, blank page has been provided at the end of this Booklet.

On receipt of the Booklet, please check that this QCA Booklet does not have any shortcomings, torn or missing pages etc. If, so, get it replaced with a fresh QCA Booklet.

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाएगा/To be filled by the Candidate)

पंजीकरण सं./Registration No. : 4612I298

अभ्यर्थी का नाम/Name of Student : VIPIN DEV YADAV

माध्यम: हिंदी/अंग्रेजी
Medium: Hindi/English

तारीख
Date
26/07/2025

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)
GENERAL STUDIES (Paper II)

केंद्र
Centre
Lucknow

निरीक्षक के हस्ताक्षर
Invigilator's Signature

	महत्वपूर्ण अनुदेश	Important Instructions
	उम्मीदवारों को नीचे उल्लिखित निर्देश सावधानी से पढ़ लेने चाहिए। किसी भी निर्देश का उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों को मिलने वाले अंकों में कटौती, उम्मीदवारी रद्द या आयोग के परवर्ती परीक्षाओं के लिए वर्जित करने इत्यादि के रूप में दण्डित किया जा सकता है।	**Candidates should read the undermentioned instructions carefully. Violation of any of the following instructions may entail penalty in the form of deduction of marks, cancellation of candidature, debarment from further Examination of the Commission etc.**
1	(क) अपना पंजीकरण सं. एवं अन्य विवरण केवल प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) में उम्मीदवार के लिए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। (ख) इस पुस्तिका में अन्यत्र कहीं भी अपना नाम, पंजीकरण सं., मोबाइल नं., पता अथवा प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका (क्यू.सी.ए.) संख्या न लिखें जिससे आपकी पहचान का खुलासा हो।	(a) Write your Registration Number and other details only in the space provided in the Question-Cum-Answer (QCA) Booklet for candidates. (b) Do not disclose your identity in any manner such as, by writing your Name, Registration number, Mobile number, Address, Question-Cum-Answer (QCA) Booklet No. etc. elsewhere in the Booklet
2	अपनी प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में कहीं भी प्रश्नों के वास्तविक उत्तर के अतिरिक्त कुछ न लिखें जैसे कि कोई कविता/दोहा, अभद्र या अपमानजनक अभिव्यक्ति इत्यादि और न ही कोई ऐसा चिन्ह/निशान बनाएं जिसका उत्तर से सम्बन्ध न हो।	Do not write in the QCA Booklet anything other than the actual answer such as couplet, obscene, abusive expression etc., nor put any sign/mark having no relevance to the answer.
3	परीक्षक को प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी प्रार्थना/धमकी भरी बातें न लिखें।	Do not make any direct/indirect appeal/threat to the examiner.
4	उत्तर अस्पष्ट अथवा गंदी लिखावट में न लिखें। इस प्रकार के उत्तर का मूल्यांकन नहीं भी किया जा सकता है।	Do not write answers in bad/illegible handwriting. Such answers may not be evaluated.
5	उत्तर स्याही में ही लिखें। उत्तर लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग न करें, हालांकि आरेख, चित्र इत्यादि बनाने के लिए पेंसिल का उपयोग किया जा सकता है।	Write answers in ink only. Do not use pencil for writing the answers. However, pencil may be used for drawing diagrams, sketches, etc.
6	प्रवेश पत्र में उल्लेख किए गए माध्यम के अलावा अन्य किसी माध्यम में उत्तर न लिखें। अधिकृत और अनधिकृत की मिली जुली भाषा का भी उपयोग न करें।	Do not write answers in medium other than the authorized medium in the Admission Certificate. Do not use mixed language either i.e. authorize and unauthorized media together for writing answers.
7	प्रश्नों के उत्तर ठीक उसके नीचे दिए गए निर्धारित स्थान पर ही लिखें। निर्धारित स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर लिखे गए उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।	Write answer at the specific space (right below the question) only. Answers written elsewhere at unspecified places in the booklet shall not be evaluated.
8	यदि आप अपने किसी उत्तर को रद्द करना चाहते हैं तो उसे पेन से काट दें तथा उस पर "रद्द" लिख दें, अन्यथा उसका मूल्यांकन किया जा सकता है।	If you wish to cancel any work, draw your pen through it and write "Cancelled" across it, otherwise it may be valued.

कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use	कार्यालय के प्रयोग हेतु For Official Use

परीक्षक के हस्ताक्षर
Signature of Examiner(s)

प्राप्तांक के विवरण (परीक्षक द्वारा भरा जाए)/ Marks Details (To be filled by the Examiner(s))

प्रश्न सं. **Q. No.**	अंक **Marks**		प्रश्न सं. **Q. No.**	अंक **Marks**	
1			**11**		
2			**12**		
3			**13**		
4			**14**		
5			**15**		
6			**16**		
7			**17**		
8			**18**		
9			**19**		
10			**20**		
उप-योग (A) **Subtotal (A)**			उप-योग (B) **Subtotal (B)**		
सकल योग (A+B) / GRAND TOTAL (A+B)					

VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

ABHYAAS MAINS

सामान्य अध्ययन (प्रश्न पत्र-II)/GENERAL STUDIES (Paper-II) (4511)

निर्धारित समय: **तीन** घंटे
Time Allowed: **Three** Hours

अधिकतम अंक: **250**
Maximum Marks: **250**

प्रश्न-पत्र संबंधी विशेष अनुदेश

कृपया प्रश्नों के उत्तर देने से पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें:

*कुल **बीस** प्रश्न दिए गए हैं जो **हिंदी** और **अंग्रेजी** दोनों में छपे हैं।*

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

प्रत्येक प्रश्न/भाग के लिए नियत अंक उसके सामने दिए गए हैं।

प्रश्नों के उत्तर उसी माध्यम में लिखे जाने चाहिए, जिसका उल्लेख आपके प्रवेश-पत्र में किया गया है, और इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न-सह-उत्तर (क्यू.सी.ए.) पुस्तिका के मुख-पृष्ठ पर निर्दिष्ट स्थान पर किया जाना चाहिए। उल्लिखित माध्यम के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम में लिखे गए उत्तर पर कोई अंक नहीं मिलेंगे।

प्रश्न संख्या 1 से 10 तक का उत्तर 150 शब्दों में तथा प्रश्न संख्या 11 से 20 तक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए।

प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखिए।

प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ भाग को पूर्णतः काट दीजिए।

QUESTION PAPER SPECIFIC INSTRUCTIONS

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions.

*There are **TWENTY** questions printed both in **HINDI** and in **ENGLISH**.*

All questions are compulsory.

The number of marks carried by a question/part is indicated against it.

Answers must be written in the medium authorized in the Admission Certificate which must be stated clearly on the cover of this Question-cum-Answer (QCA) Booklet in the space provided. No marks will be given for answers written in a medium other than the authorized one.

Answers to Questions No. 1 to 10 should be in 150 words, whereas answers to Questions No. 11 to 20 should be in 250 words.

Keep the word limit indicated in the questions in mind.

Any page or portion of the page left blank in the Questions-cum-Answer Booklet must be clearly struck off.

EVALUATION INDICATORS

1. **Contextual Competence**
2. **Content Competence**
3. **Language Competence**
4. **Introduction Competence**
5. **Structure - Presentation Competence**
6. **Conclusion Competence**

Overall Macro Comments / feedback / suggestions on Answer Booklet:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

All the Best

1. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर उच्चतम न्यायालय का हालिया निर्णय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 की व्याख्या को कैसे प्रभावित करता है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)
How does the Supreme Court's recent decision on Aligarh Muslim University's minority status affect the interpretation of Article 30 of the Indian Constitution? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

अनु० 30 अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रबंधन का अधिकार देता है।

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संबंध में निर्णय दिया है—

(i) यह जरूरी नहीं है कि शिक्षण संस्थानों का प्रबंधन अल्पसंख्यक करे तो ही वह संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान कहलाएगा।

(2) किसी संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि वह किसी कानून द्वारा स्थापित है।

(3) यदि कोई समुदाय स्वतंत्रता पश्चात अल्पसंख्यक की श्रेणी में आता है तो स्वतंत्रता पूर्व के शिक्षण संस्थानों के लिए अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा माँगा सकता है।

VisionIAS

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

अनु 30 पर प्रभाव

(i) पूर्व में सीरियन कैथोलिक कॉलेज वाद में उच्चतम न्यायालय ने अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रशासन के कुछ मानदंड स्थापित किए थे।

(ii) वर्तमान का निर्णय अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थापना को कोई आधिक शक्ति देता है।

(iii) अब केवल मंशा (Intention) को ही आधार मानकर अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है।

(iv) इससे उच्चतम न्यायालय में वादों की संख्या में इजाफा हो सकती है (संस्थान को दर्जा मानने)

(v) अनु 30 का व्यापक विस्तार संभव।

अतः भारत की विविधता के हिसाब से यह जरूरी है कि अल्पसंख्यकों के हितों का पर्याप्त संरक्षण हो।

VisionIAS

2. उच्चतम न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में राज्य विधान-मंडल के विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति के लिए एक समय-सीमा निर्धारित की है। इस निर्णय के भारत में सहकारी संघवाद और विधायी जवाबदेही के लिए क्या निहितार्थ हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

The Supreme Court, in a recent verdict, prescribed a time period for the Governor's assent to state legislative bills. What are the implications of this judgment for cooperative federalism and legislative accountability in India? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु राज्यपाल वाद में राज्य विधेयकों को राज्यपाल को स्वीकृति देने की समय सीमा तय की है।

राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की शक्ति

अनु॰200 ⇒ राज्यपाल विधेयक को स्वीकार, सुरक्षित, अस्वीकार, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। या राष्ट्रपति को आरक्षित कर सकते हैं।

अनु॰201 ⇒ राष्ट्रपति को राज्य विधेयकों के सन्दर्भ में शक्ति

हालिया निर्णय ⇒ मंत्रिपरिषद के साथ परामर्श के सम्बन्ध में ⇒ 1 माह

↳ विवेकाधिकार का प्रयोग करने पर = 3 माह

→ राज्य विधेयकों पर राज्यपाल व राष्ट्रपति के पास आत्यांतिक या पॉकेट वीटो नहीं है।

सहकारी संघवाद पर प्रभाव

(i) राज्यपाल के शक्तियों पर

VisionIAS

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उस सीमा तक प्रतिबंध।

(2) राज्यपाल व राज्य मंत्रिमंडल के मध्य संघर्ष को बढ़ावा।

(3) न्यायिक अतिक्रमण का हालिया निर्णय पर प्रभाव.

(4) केन्द्र-राज्य के मध्य टकराव
केन्द्र व राज्य विधेयकों के संदर्भ में शक्ति में कमी।

विधायी जवाबदेही => (i) राज्यपाल के विवेकाधीन शक्तियों पर प्रतिबंध
विधायिका पर दबाव में कमी.
जवाबदेहिता कमी.
विधानों के निर्माण में मनमानी चल सकती है।

उपाय =) सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना (पेनावेल आयोग)
-) राज्यपाल को अनावश्यक राज्य विधायिका सरकार की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।
-) सहयोग, समायोजन, समन्वय बढ़ाना चाहिए।
-) विधेयकों के लिए जवाबदेह बनना।

अतः केन्द्र-राज्य विवादों का समाधान कर ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

3. सहकारी क्षेत्रक में केंद्र और राज्यों के बीच के गतिरोध को कम करने के उद्देश्य से किए गए सहकारी संस्थाओं से संबंधित हालिया परिवर्तनों और पहलों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Discuss the recent changes and initiatives related to cooperatives that aim to smoothen the tussle between the Centre and States in the cooperative sector. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

सहकारी क्षेत्रक का वर्णन

97th संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के अनु० 19(c), 43B, भाग IXB 243ZH-ZT में किया गया है।

केन्द्र व राज्य के बीच गतिरोध

(i) 97th CA - राज्य की अधिकारिता में हस्तक्षेप के रूप में देखा गया (उच्चतम न्यायालय निर्णय → 97th बहुराज्य सहकारी समिति पर प्रभावी)

(2) सहकारिता मंत्रालय ⇒ राज्य की शक्ति पर केन्द्र का अतिक्रमण

(3) बहुराज्य सहकारी समिति अधि० 2023 ↓ राज्य पर विनियमन को मजबूत करना।

(4) सहकारी क्षेत्रक के पास वित्त, कुशल कर्मचारी, आधुनिक तकनीक का अभाव।

(5) केन्द्र - राज्य की नीतियों में ओवर लैपिंग

VisionIAS

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

हालिया परिवर्तन एवं पहल

(i) संविधान संशोधन (97th)

(2) बहुराज्य सहकारी समिति अधिo में संशोधन

(3) सहकारी विकास निगम

(4) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण मानदण्ड में सहकारी समिति शामिल

(5) श्वेत क्रांति 2.0 में सहकारी समितियों के विकास पर बल।

(6) किसान उत्पादक संगठनों के निर्माण पर बल।

(7) PACs के स्तर पर विश्व की सबसे बड़ी अनाज भण्डारण योजना व PACs का आधुनिकीकरण

(8) 'सहकार से समृद्धि' का स्लोगन

(9) 2025 — अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष।

अतः सहकारिता विकसित भारत के निर्माण की कुंजी हैं। अत इसके समक्ष विभिन्न मुद्दों का समाधान केन्द्र-राज्य को मिलकर करना चाहिए।

4. हाल के वर्षों में, नागरिक समाज द्वारा सोशल मीडिया और डिजिटल लामबंदी का उपयोग दबाव की राजनीति के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरा है। नीति-निर्माण और लोकतांत्रिक जवाबदेही पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

In recent years, use of social media and digital mobilisation by civil society has emerged as a powerful form of pressure politics. Examine its impact on policymaking and democratic accountability. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

नागरिक समाज व्यक्तियों के समूह है। जो सामाजिक मुद्दों का समाधान करने के लिए, सरकारी नीतियों को प्रभावित करने के लिए साथ आते हैं।

अ. उदा० => NGO, दबाव समूह आदि।

सोशल मीडिया व डिजिटल लामबंदी

(i) प्रथम NGO द्वारा हिंसा के विरोध में लोगों का सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदर्शन।

(2) वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, PETA द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण के लिए डिजिटल लामबंदी!

नीति निर्माण पर प्रभाव

(i) नीति निर्माण के लिए गुणवत्ता पूर्ण डाटा, जनसमस्याओं की पहचान उदा० => आक्सफैम

(2) जनता - सरकार के मध्य सेतु का कार्य।

VisionIAS

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(3) सरकार को सलाह प्रदान करना (हेल्पिंग डायेरशन)

(4) नीतियों के क्रियान्वयन में सरकार की सहायता करना

अक्षय पात्र ⇒ पोषण कार्यक्रम का क्रियान्वयन।

लोकतांत्रिक जवाबदेही पर प्रभाव

(1) शासन व्यवस्था में पारदर्शिता, दक्षता, जवाबदेहिता लाना व जनता को जागरूक करना (इंस्टीट्यूशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स)

(2) गवर्नेंस संबंधी समस्याओं को विधिक तरीके से सुलझाना (कामनकाज PUCL

नागरिक समाज का राजनीतिकरण का आरोप ← मुद्दे
→ कुछ नागरिक समाज पर विदेशी फंडिंग का अवैध रूप में प्रयोग करने का आरोप
→ विकास परियोजनाओं में बाधा डालना
ग्रीनपीस इंटरनेशनल

अतः विधिक नीतिगत फ्रेमवर्क व विभिन्न हितधारकों के समन्वय से नागरिक समाज के लाभों को प्राप्त किया जा सकता है।

VisionIAS

5. भारत में विकास संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व किस प्रकार एक व्यवसाय-प्रेरित समाधान के रूप में उभर रहा है? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

How is Corporate Social Responsibility (CSR) emerging as a business-led solution for addressing development challenges in India? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का तात्पर्य बड़ी कम्पनियों द्वारा समाज के प्रति अपने दायित्वों कर्तव्यों का निर्वहन।

कल्याणकारी राज्य सामाजिक न्याय की अवधारणा के अनुरूप

CSR
→ ट्रस्टीशिप की अवधारणा के अनुरूप
→ कम्पनी अधि० 2013 में प्रावधान
→ कंपनी का नेट वर्थ 500 करोड़ - टर्नओवर 1000 करोड़ तथा लाभ 5 करोड़ हो

तीन वर्ष के औसत लाभ का 2% सामाजिक उद्देश्य में

विकास संबंधी चुनौतियाँ

1. क्षेत्रीय विषमता => पूर्वी भारत पूर्वोत्तर सेग पिछड़ा
2. मूलभूत सुविधा अवसंरचना का अभाव = शिक्षा स्वास्थ्य कौशल
3. आय की असमानता (आर्थिक => 1% => 40% लोगों 50% => 3%)
4. विकास योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार
8. योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी।

VisionIAS

CSR का महत्व

(i) क्षेत्रीय विषमता को कम करना
⇓
IOCL SC/ST छात्रों को छात्रवृत्ति

(2) कुशल मानव संसाधन का निर्माण => टाटा फाउंडेशन => स्कूल/कालेज
└ इन्फोसिस विप्रो शिक्षा।

(3) पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा
⇓
हिंदुस्तान पेट्रोलियम बूंद कार्यक्रम

(4) ग्रामीण विकास

(5) महिला सशक्तीकरण => जागरूकता प्रशिक्षण

(6) कंपनियों को लाभ
→ ग्राहक आधार में विस्तार
→ विश्वसनीयता में वृद्धि
→ बाजार विस्तार
→ निवेश, नवाचार को बढ़ावा

व्यवसाय का लाभ होगा

चुनौतियां => CSR का आडिट का अभाव
→ स्वयं द्वारा स्थापित NGO द्वारा CSR
→ आवश्यक गतिविधियां महाराष्ट्र गुजरात तक सीमित
→ मुख्य फोकस - शिक्षा स्वास्थ्य

अतः CSR गतिविधियों की आडिटिंग CSR बोर्ड की स्थापना व विभिन्न हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित कर सामाजिक न्याय, समावेशी विकास को प्राप्त किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

VisionIAS

6. चर्चा कीजिए कि भारत में जन परामर्श और जन सुनवाई जैसे तंत्र गवर्नेंस के परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Discuss how mechanisms like public consultations and Jan Sunwais in India impact governance outcomes. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत में सुशासन का महत्वपूर्ण पहलू जन भागीदारी होती है।

जन परामर्श व जनसुनवाई प्रभाव

(i) नीतियों का प्रभावी निर्माण करने के लिए लोगों से संबंधित मुद्दे जन परामर्श से प्राप्त होते हैं

mygov.in पोर्टल => सुझाव
⇓
स्वच्छ भारत मिशन में

(2) नीतियों के क्रियान्वयन के लिए
⇓
फीड-बैक प्राप्त होता
⇓
सोशल आडिट
⇓ मनरेगा PDS

जन सुनवाई => नौकरशाही को जवाबदेह बनाना
शासन में पारदर्शिता।
भागीदारी [illegible]

VisionIAS

- भ्रष्टाचार के मामले उजागर होंगे
- लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होगा।
- लोगों का शासन में विश्वास बढ़ेगा!

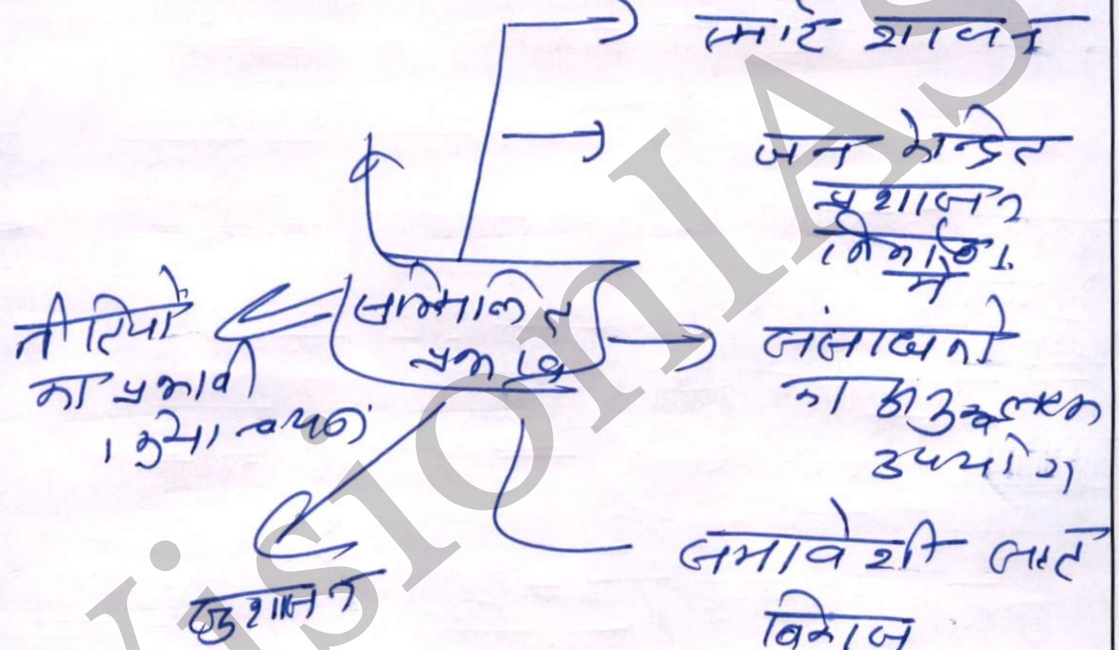

अत: लोकपाल लगातार जवाबदेहिता बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

7. भारत में मादक द्रव्यों के दुरुपयोग की समस्या से निपटने में राष्ट्रीय मादक द्रव्य मांग न्यूनीकरण कार्य योजना और नशा मुक्त भारत अभियान कितने प्रभावी रहे हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

How effective have the National Action Plan for Drug Demand Reduction (NAPDDR) and Nasha Mukt Bharat Abhiyaan been in addressing substance abuse in India? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

VisionIAS

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

VisionIAS

8. भारत की बुनियादी शिक्षा प्रणाली में रटकर सीखने की प्रवृति और रचनात्मकता की उपेक्षा, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित हो रहे बाज़ारों के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं करती हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने तर्क से उत्तर की पुष्टि कीजिए। (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Rote learning and neglect of creativity in foundational education setup in India make it less ready for marketplaces that are now driven by Artificial Intelligence. Do you agree with this view? Substantiate your argument. (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

शिक्षा वह शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग आप विश्व को बदलने के लिए कर सकते हैं।

मेरा तर्क पक्ष

(1) भारत में शिक्षा सैद्धान्तिक
→ यथास्थितिवादी
→ बनावट दायरा का निर्माण
→ नवाचार, गतिशीलता का अभाव

(2) रोजगार के लिए ऐच्छिक तैयार करना

(3) आउटकम पर ध्यान देना

AI के लिए → व्यवहारिक शिक्षा चाहिए
→ उद्देश्य द्वारा
→ तकनीकी रूप से दक्ष।

VisionIAS

सरकारी प्रयास

1. नई शिक्षा नीति 2020
2. वैभव
3. इन्स्टीट्यूट ऑफ एमीनेंस पर ध्यान
4. विदेशी विश्वविद्यालयों की भागीदारी बढ़ाना

अतः भारत में शिक्षा को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप बनाना आवश्यक है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

VisionIAS

9. G7 के पश्चिमी रणनीतिक एकता के प्रतीक से आंतरिक विरोधाभासों से भरे मंच के रूप में रूपांतरण का विश्लेषण कीजिए। भारत द्वारा अपने रणनीतिक हितों की पूर्ति हेतु इस बदलते परिदृश्य को किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिए? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Analyze the transformation of the G7 from a symbol of Western strategic unity to a forum marked by internal contradictions. How should India navigate this changing dynamic to advance its strategic interests? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

G-7 मुख्यतः विशेषता

लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधि

जिसमें अमेरिका, कनाडा, जर्मनी,

इटली, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन,

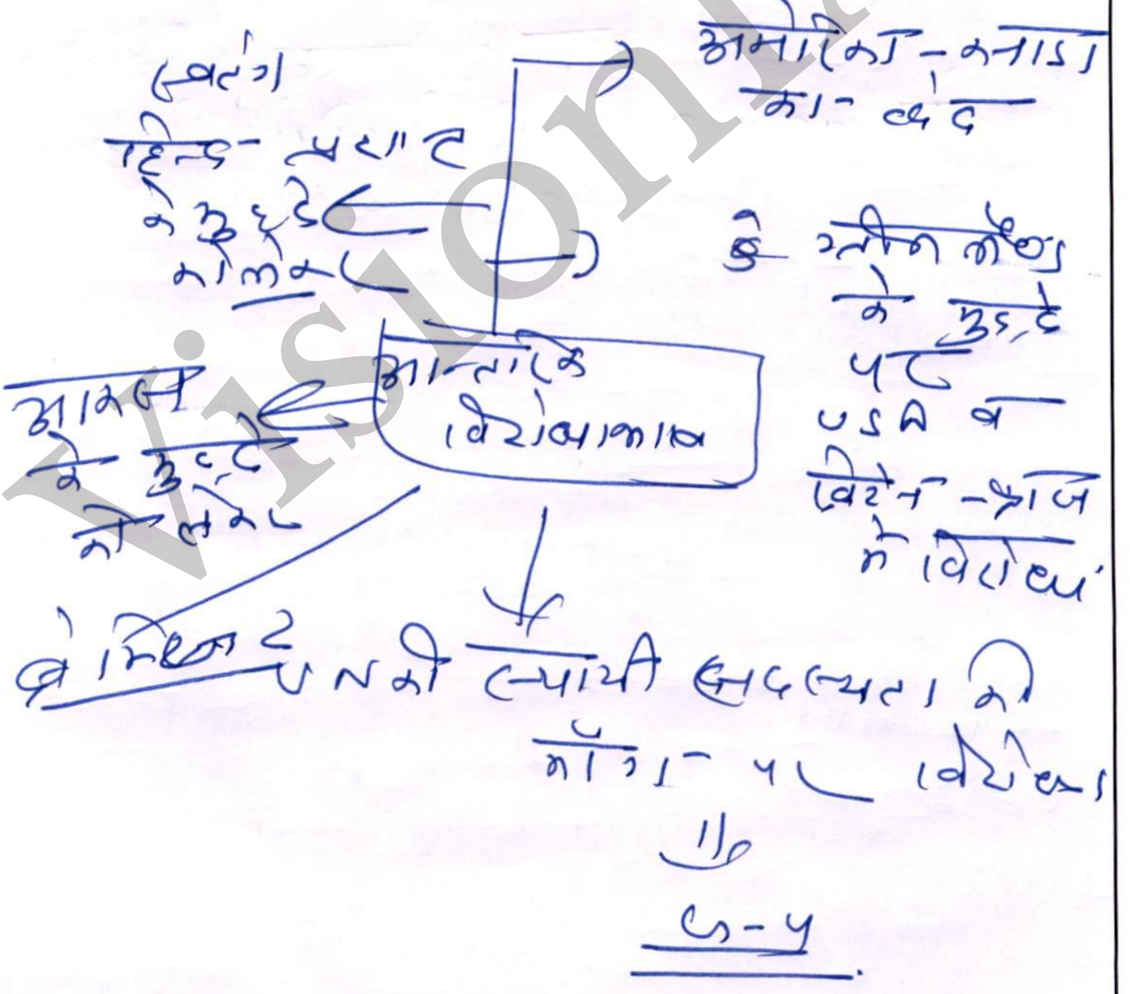

VisionIAS

क्वाड => बहुध्रुवीयता को बढ़ावा

→ रणनीतिक मामलों के आधार पर संबंध निर्धारण

→ द्विपक्षीय, बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ावा

उदा. I2U2 – क्वाड-प्लस – मालाबार

→ कोरोनावैक्सीन पर ध्यान

G-7 => बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड

PGII

→ अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में हितों के अनुसार परिवर्तन

ज्वलंत उदाहरण

अतः क्वाड को संयुक्ता का महत्व देते हुए जुगान [illegible] बहुध्रुवीय दुनिया में कायम रखना

VisionIAS

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

10. विकासशील देशों के विकास में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका पर चर्चा कीजिए। इसके दृष्टिकोण से जुड़ी प्रमुख आलोचनाएं क्या हैं? (उत्तर 150 शब्दों में दीजिए)

Discuss the role of the International Monetary Fund (IMF) in the development of developing countries. What are the key criticisms associated with its approach? (Answer in 150 words) 10

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

IMF प्रेरणाकारक संस्था है

IMF
→ वित्त प्रदान करना
→ वित्तीय स्थिरता निर्धारण
→ SDR निर्माण
→ ड्रॉइंग कोटा प्रदान करना
→ वित्तीय शासन मॉनिटरिंग
→ राजकोषीय नीति अनुशासन

आलोचना
→ पश्चिमी देशों के प्रभाव का आरोप
→ ~~निरंतर~~ नवउदारवादी दृष्टिकोण नकारात्मक

निष्कर्ष

VisionIAS

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

VisionIAS

11. 103वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 ने भारत में सकारात्मक कार्रवाई के सिद्धांत को एक नया आयाम दिया है। सामाजिक न्याय के व्यापक लक्ष्य के लिए इसके निहितार्थों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The 103rd Constitutional Amendment Act, 2019 has introduced a new dimension to the principle of affirmative action in India. Critically examine its implications for the broader goal of social justice. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सकारात्मक कार्यवाही महत्वपूर्ण उपकरण है। जिसका प्रमुख पहलू है आरक्षण।

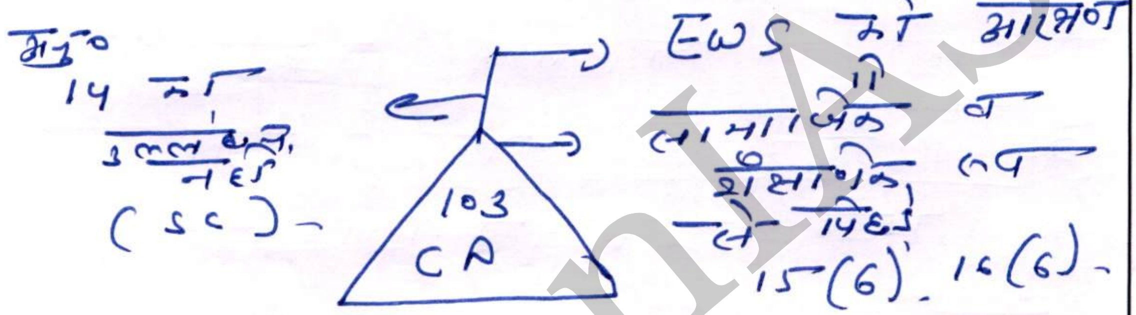

आवश्यकता ⇒ पूर्व में आरक्षण को ऐतिहासिक वंचना, शोषण के उपचार का माध्यम माना गया।
→ 103 CA ने इसे आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर सामान्य वर्ग तक विस्तारित कर दिया।

महत्व ⇒ (i) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक विशेष रूप से विभिन्न सुविधाओं की पहुँच
(2) रोजगार तक प्रभावी पहुँच
(3) शिक्षा के लिए विशेष कार्यक्रम

VisionIAS

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(4) इन वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।

(5) वंचना की भावना समाप्त होगी

(6) हक व अधिकार मिलेगा।

(7) सामाजिक न्याय का लक्ष्य पूरा होगा।

चुनौतियाँ → (i) इन्द्रा साहनी वाद में आरक्षण की सीमा 50% 103 CA में इसका अतिक्रमण कहाँ, OBC SC ST में आरक्षण बढ़ाने की माँग।

(2) आरक्षण शोषण भेदभाव को मिटाने के लिए लाया गया था न कि गरीबी निवारण।

(3) आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सरकार की अन्य योजनाएं चल रही हैं। अत: आरक्षण राजनीतिक लाभ रेवड़ी का अंग बन चुका है।

(4) आरक्षण के मुद्दे का राजनीतिकरण सौहार्दपूर्ण माहौल खराब होगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

समाधान (i) जातिगत जनगणना
↓
सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन ⇒ गुणवत्तापूर्ण डाटा की उपलब्धता

(2) जातियों का उपवर्गीकरण
↓
दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद

(3) आरक्षण के प्रभावों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन

(4) आरक्षण में SUNSET CLAUSE का प्रावधान लागू करना।

(5) आर्थिक लेन 'कैपिटेबल अप्रोच' को लागू करना।

(6) उत्तर विकल्प, के माध्यम को प्रभावी दक्ष तरीके से लागू करना।

अतः सकारात्मक कार्यवाही कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य, सामाजिक न्याय के लिए अनिवार्य है। परन्तु इसका समय-2 पर मूल्यांकन इसकी प्रभाविता बढ़ाने के लिए जरूरी है।

VisionIAS

12. जिला योजना समिति की परिकल्पना जमीनी स्तर पर नियोजन को सशक्त बनाने के एक प्रमुख साधन के रूप में की गई थी। यह इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी सफल रही है? जिला योजना समितियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिए तथा उन्हें अधिक प्रभावी बनाने के उपाय सुझाइए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

The District Planning Committee (DPC) was envisioned as a key instrument to strengthen grassroots-level planning. How far has it succeeded in achieving this goal? Discuss the challenges faced by DPCs and suggest measures to make them more effective. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

जिला योजना समिति का गठन 74th संविधान संशोधन के माध्यम से की गई थी। जिसका उद्देश्य नियोजन को प्रभावी तौर पर लागू करना था।

जिला योजना समिति => पंचायत व नगरीय निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधि शामिल होते हैं
- कार्यकारी शीर्ष अधिकारी भी शामिल।

महत्व => (1) ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों के बीच सहयोग, समांजस्य व समन्वय बढ़ेगा।

(2) अधिकारों दायित्वों में ओवर लैपिंग की समस्या कम होगी,

(3) ग्रामीण - शहरी सातत्य के आधार पर नीतियों, योजनाओं का निर्माण => योजनाओं की प्रभावशीलता दक्षता बढ़ेगी।

VisionIAS

(4) संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होगा।

(5) जवाबदेहिता, पारदर्शिता जैसी बाधाए कमजोर होगी।

(6) समग्र विकास को बढ़ावा।

(7) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण व समावेशी नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति।

चुनौतियां ⇒ (1) कार्यकारी व निर्वाचित प्रतिनिधियों के मध्य समन्वय का अभाव।

(2) ग्रामीण - शहरी क्षेत्रों की समस्याए, सम्भावनाए अलग-2 होते हैं अतः 'वन साइज फिट फार आल' अप्रोच उपयुक्त नहीं।

(3) संसाधनों के आवंटन को लेकर राजनीति ⇒ पर्याप्त फंड का अभाव

(4) जिला नियोजन समिति की नियमित मीटिंग न होना।

(5) कर्मचारियों/प्रतिनिधियों को दायित्वों की पूर्ण जानकारी का अभाव

(6) समिति के कार्यों का विभिन्न राज्यों में अलग-2 नियम।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin
VisionIAS

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

समाधान

(1) जिला नियोजन समिति की संरचना में सुधार
स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं, विषय विशेषज्ञों, NGO को शामिल करना

(2) 'कामन मिनिमम प्रोग्राम' को बढ़ावा

(3) तार्किक बहस को बढ़ाना।

(4) नियोजन समिति अपने विभिन्न कार्यों को छोटी-2 समितियों के माध्यम से कर सकती है,

(5) नीतियों योजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन की प्राथमिकता तय करना।

(6) योजनाओं के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग।

(7) जिला नियोजन समिति के प्रदर्शन का मूल्यांकन।

अतः जिला नियोजन समिति को विभिन्न बाधाओं से मुक्त कर जमीनी-स्तरीय विकास को एक सूत्र में बांधा जा सकता है

VisionIAS

13. संविधान के अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों की उधार लेने की शक्तियों पर लगाए गए प्रतिबंध, यद्यपि संवैधानिक रूप से वैध हैं, लेकिन ये राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता को बाधित कर सकते हैं और सहकारी संघवाद को क्षति पहुंचा सकते हैं। हालिया घटनाक्रमों के आलोक में विवेचना कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)
The restrictions imposed under Article 293 of the Constitution on State borrowing powers, though constitutionally valid, may hinder fiscal autonomy of States and disrupt cooperative federalism. Discuss in the light of recent developments. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

राजकोषीय संघवाद से तात्पर्य केन्द्र-राज्य-स्थानीय निकायों के मध्य वित्त व प्राधिकार का वितरण।

राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता व सहकारी संघवाद को बाधित करनेवाले कारक

(1) राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 3% से अधिक ऋण नहीं ले सकते।

└ अनु. 292 के अनुसार संघ आन्तरिक व विदेशों से ऋण प्राप्त कर सकता है।

└ अनु. 293 => राज्यों को विदेशों से ऋण लेने से प्रतिबंधित किया गया है।

(1) राज्यों को स्वायत्तता के लिए।
(2) केन्द्र-राज्य संबंधों के लिए
(3) राष्ट्र की एकता अखण्डता को सुनिश्चित करने के लिए

(बाधा) => राज्य के ऋण लेने के लिए स्रोत सीमित।

VisionIAS

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

- आंतरिक रूप से भी संस्था स्थापित नहीं कर सकते यदि स्रोत का अभाव हो।
- राज्यों की वित्तीय स्थिति चिंताजनक होती है।
- केंद्र द्वारा सेस व सरचार्ज (कुल कर संग्रह का 25%) का वितरण राज्यों के साथ नहीं किया जाता है।
- GST के संदर्भ में केंद्र के पास आर्थिक शक्तियाँ।
- इससे केंद्र-राज्य विवाद बढ़ता है। सहकारी संघवाद की भावना कमजोर होती है,

समाधान => (1) राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता

(2) वित्तीय स्रोतों में विविधता।

(3) राजकोषीय निष्पादन को बढ़ावा देना (15 वित्त आयोग 2.5%)

(4) सेस व सरचार्ज पर निर्भरता में कमी

VisionIAS

(5) अन्तर्राज्यीय परिषद की नियमित बैठक => राज्यों के उद्गारों का समाधान हो।

(6) निजी निवेश को बढ़ावा देना।

(7) राज्यों में अवसंरचना सुधार को बढ़ावा देना।

(8) राज्यों की अतार्किक खर्च पर रोक उदा० => फ्रीबीज राजकोष व्यय।

(9) केंद्र द्वारा राज्यों की विनिर्माण सेक्टर की मॉनिटरिंग के लक्ष्य-स्वभाव देना।

(10) स्थायी वित्त आयोग => कार्यालय => व्यापकता। केंद्र-राज्य विवादों का समाधान करेगा।

समावेशी विकास विकसित भारत @ 47 के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है,

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

VisionIAS

14. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव लड़ने के अधिकार और चुनावी नैतिकता बनाए रखने की आवश्यकता के बीच के तनाव का परीक्षण कीजिए। क्या दोषसिद्ध अपराधियों पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Examine the tension between the right to contest elections and the need to uphold electoral ethics under the Representation of the People Act. Should there be a lifetime ban on convicted criminals? (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

चुनाव लोकतंत्र का मूल आधार है। इस प्रणाली को व्यवस्थित करने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, 1951 लाया गया।

चुनाव लड़ने का अधिकार

(i) अर्हता का निर्धारण
- लोकसभा के लिए 25 वर्ष
- भारत का नागरिक
- भारतीय सीट के लिए भारतीय लद्दाख का सदस्य

(2) निर्हता का आधार
- दिवालिया न हो
- संसद में लेख, हेट स्पीच कंपनी के लिए आरोपी न ठहराया गया हो।
- निर्धारित समय में चुनाव खर्च का ब्यौरा दिया हो
- भ्रष्टाचार के आरोप में सेवा से न हटाया गया हो
- 2 वर्ष की सजा न हुई हो।

ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है।

चुनावी नैतिकता ⇒ चुनाव लड़ने मतदान करने व अन्य प्रक्रियाओं को

VisionIAS

नैतिक मूल्यों का समावेश रहता

(दंड)

- राजनीति का अपराधीकरण
  ADR => 16LS => 46%
  (रुपराधी)
- जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने से रोकती है। आरोपी को नहीं
- राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी।
- खुलेआम चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है।
- टेढ़ नीचे का मजबूत घोषणी
  अत: यह कदम लगातार सामने आता है।

रोक लगाई अपराधियों पर चुनाव प्रतिबंध के तर्क

(1) अपराधी - अपराधी होता है। चाहे 2 साल हो या 20 साल।

(2) नेताओं में भय युक्त संस्कृति का विकास करता है (अभी माना जाता है कि बाद में चुनाव लड़ लेंगे)

(3) राजनीति में अपराधीकरण को रोकेगा।

(4) युवाओं के राजनीति में प्रवेश के मार्ग में सहायक होगा।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

VisionIAS

⑤ धन बल, बाहुबल का प्रभाव कम होगा।

विपक्ष में तर्क ⇒ (i) कुछ मामले राजनीतिक द्वेष के आधार पर लगाए जाते हैं। अतः यह निष्पक्ष न्याय की प्रक्रिया का उल्लंघन होगा।

② यह दोष सिद्धि के पहले लम्बे अवधि तक चुनाव के मामले का समाधान नहीं करता है।

③ अभी सत्ता पक्ष को विरोध करने वाले प्रतिपक्ष को विरोध जैसी भावना समाज → लोकतांत्रिक मूल्य → हिंसा, गाली गलौज, बाहुबलिक कमजोर

समाधान ⇒ फास्ट ट्रैक कोर्ट राजनीति के अपराधियों के मुद्दों का तत्काल समाधान

→ साक्ष्य एकत्रित करना
→ FCI को सशक्त करना

जनता को जागरूक करना (सिविल सोसाइटी की भूमिका ।, मीडिया, सोशल मीडिया।

अतः राजनीति के अपराधीकरण को रोककर ही लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए Candidates must not write on this margin

VisionIAS

15. 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना घटते बाल लिंगानुपात को सुधारने और बालिकाओं को सशक्त बनाने में किस हद तक सफल रही है? जमीनी स्तर पर इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए उपाय सुझाइए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

To what extent has the Beti Bachao Beti Padhao (BBBP) scheme, launched in 2015, succeeded in addressing the declining child sex ratio and empowering the girl child? Suggest measures to enhance its impact at the grassroots level. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हरियाणा के पानीपत जिले से प्रारम्भ किया गया था। जिसका उद्देश्य सेवाओं लक्ष्य SDG 4, 5, 21 को प्राप्त करना था।

महत्व => (i) गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व लिंग जाँच निषेध अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया।

↓ भ्रूण हत्या में कमी

↓ बाल लिंगानुपात में सुधार हुआ।

(2) बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन

- जागरूकता ↓
- प्रोत्साहित कर

↓ स्कूल नामांकन दर में सुधार

(3) बालिकाओं के पोषण पर भी ध्यान दिया गया (पोषण अभियान 2.0)

(4) बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण।

VisionIAS

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

(5) वन स्टाप सेन्टर => पीड़िताओं का तत्काल समाधान
(6) SHE बाक्स
(7) POSCO 2012, POSH 2013 का प्रभावी क्रियान्वयन.

परन्तु अभी भी कुछ समस्याएं व्याप्त है।
(1) भ्रूण हत्या (कुछ जाँच सेन्टर पर है, सम्पन्न व्यक्ति के लोग है)
(2) बेटियों को घर का कार्य साथ ही पढ़ाई करनी पड़ती है (CIEEP नाम)
(3) अभी भी निम्न स्तर एवं बालिका शिक्षा के सम्बन्ध में जागरूकता की कमी है।
(4) बलात्कार जैसी घटनाएं इस योजना पर प्रश्नचिह्न लगाती हैं। कोलकाता डा० आर.जी.कर मामला.
(5) लोकसभा सदस्या => लगभग 50% महिलाएं पंचायत के बीच
(6) कार्यस्थल पर यौन शोषण की घटनाएं
(7) शिक्षा व्यवस्था का अभाव

VisionIAS

व उनकी आवाज देगा जो आर्थिक दूरी

समाधान → (1) लोगों की मानसिकता को बदलना।
मीडिया, सिनेमा, लोकगीत आदि.

(2) ग्राम सभा की भूमिका को बढ़ाना

(3) तकनीकी नवाचार को बढ़ावा तथा डिजिटल गैप को कम करना
टेली एजुकेशन

(4) विधानों का सफल क्रियान्वयन
जैसे POSH 2013.

(5) बालिकाओं को छात्रवृत्ति, डिजिटल डिवाइस प्रदान करना।

(6) तत्काल न्याय तक पहुंच का प्रावधान करना, => महिला पुलिस,

अत: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आदि के समग्र आर्थिक विकास का व सतत विकास लक्ष्य 5 प्राप्त करने का महत्वपूर्ण उपकरण है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

VisionIAS

16. स्वयं-सहायता समूह ग्रामीण भारत में सामाजिक-आर्थिक कायाकल्प के चालक के रूप में उभर रहे हैं। उनकी पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाने में सरकार की भूमिका का परीक्षण कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Self-Help Groups (SHGs) are emerging as vehicles of socio-economic transformation in rural India. Examine the role of government in scaling their reach and effectiveness. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

स्वयं सहायता समूह समान सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों का समूह होते हैं, जो आपसी बचत एक दूसरे को सहायता कर समस्याओं का समाधान करते हैं।

उदा० ⇒ सेवा (सेल्फ एम्प्लायड वुमेन एसोसिएशन) → इलाबेन

ग्रामीण भारत के सशक्तीकरण के भूमिका

(i) वित्तीय समावेशन को बढ़ावा।

(2) बचत की संस्कृति को बढ़ावा

(3) स्वरोजगार को बढ़ावा
उदा० ⇒ लिज्जत पापड़
- आय में वृद्धि
- आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर
- अपने जीवन से जुड़े निर्णयों को लेने में सक्षम।
- महिला सशक्तीकरण।

(4) शिक्षा स्वास्थ्य एवं अन्य मामले

सुविधाओं तक पहुँच

बिहार की जीविका दीदी

(5) खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना
⇓
कुटुम्बश्री

(6) कृषि विकास को बढ़ावा देना व तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करना
⇓
नमो ड्रोन दीदी

सरकार की भूमिका

(i) SHG का पंजीकरण
(2) नाबार्ड द्वारा SHG - बैंक लिंकेज कार्यक्रम => SHG की वित्तीय जरूरत को पूरा किया जा सकता
(3) दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन
⇓
SHG को सशक्तिकरण।

चुनौतियाँ => (i) SHG में नेतृत्व का अभाव
(2) पितृसत्तात्मक मानसिकता व दोहरा कार्यबोझ को बाधा करना
(3) वित्त का अभाव
(4) डिजिटल डिवाइड व जागरूकता का अभाव

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin
VisionIAS

(5) फण्ड का अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना

(6) जातिगत बाधाएं ⇒ आपसी सहयोग एकता को प्रभावित करती है

(7) नौकरशाही की मानसिकता, लालफीताशाही, गोपनीयता ⇒ SHGs के कार्य में बाधा

समाधान

- → SHG का विनियमन पंजीकरण
- → फंड तक पहुंच
- → प्रशिक्षित करना
- → नेतृत्व क्षमता विकसित करना
- PSL मानदण्डों में शामिल
- SHGs के विकास के लिए समर्पित नीति व इकाई का गठन
- नौकरशाही का विकेन्द्रीकरण, SHG की भागीदारी, सौबद्धता

अतः SHGs का सर्वांगीण विकास कर ग्रामीण महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर सामाजिक न्याय व कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

VisionIAS

17. आर्थिक संवृद्धि के बावजूद, भारत में बहुआयामी निर्धनता बनी हुई है। इसके अंतर्निहित कारणों का विश्लेषण कीजिए और उन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों पर चर्चा कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Despite economic growth, multidimensional poverty continues to persist in India. Analyse the underlying causes and discuss the measures taken by the government to address them. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

गरीबी हिंसा का क्रूरतम रूप है। विश्व बैंक के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का प्रतिदिन उपभोग 2.15$ से कम है। तो वह चरम गरीबी की स्थिति में है।

गरीबी
- आय आधारित गरीबी
- बहुआयामी गरीबी (शिक्षा, स्वास्थ्य आदि)
- सापेक्षिक गरीबी (गिनी गुणांक, लॉरेंज वक्र)
- निरपेक्ष (मूलभूत आवश्यकता पूर्ण नहीं)

- भारत विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- अर्थव्यवस्था का आकार 4.1 ट्रिलियन $ लगभग है।
- अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर 6.4% है।
- निर्यात लगभग 778 Bn$ है।
- विश्व में सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करता है

VisionIAS

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

फिर भी गरीबी बनी हुई है —

नीति आयोग => राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2023 => 11.28%

कारण => (i) गरीबी की वास्तविक परिभाषा व गरीबों के पहचान का अभाव,

(2) रोजगार विहीन विकास (PLFS 2023-24, 3.1%)

(3) आय की असमानता
ऑक्सफैम — 1% → 40%
— नीचे 50% => 3%

(4) कृषि का पिछड़ापन

(5) योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार
PDS => 28% लीकेज

(6) उच्च जनसंख्या (UNFPA)
1st = 146.9 करोड़

(7) अकुशल जनसंख्या

(8) सरकार की नीतियाँ दान आधारित न कि सशक्त आधारित (फ्रीबीज)

सरकार के प्रयास (1) नई शिक्षा नीति 2020
(2) समग्र शिक्षा अभियान
(3) मध्याह्न भोजन कार्यक्रम
(4) आयुष्मान भारत योजना
(5) डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

उदाहरण
- PM जन धन योजना
- PM आवास योजना
- स्वच्छ भारत मिशन
- जल जीवन मिशन
- PM उज्ज्वला योजना।
- स्वामित्व योजना।
- PM गरीब कल्याण अन्न योजना।
- NFSA 2013
- मनरेगा कार्यक्रम
- PM किसान सम्मान निधि
- PM कृषि सिंचाई योजना।

अतः भारत सरकार लगातार गरीबी निवारण सम्बन्धी तहत निर्धनता को समाप्त करने व SDG 1 को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

VisionIAS

18. भारत खाद्य अधिशेष और पोषण की कमी संबंधी विरोधाभास का सामना कर रहा है। इस विरोधाभास के पीछे निहित संरचनात्मक कारणों का विश्लेषण कीजिए और सुधार हेतु रणनीतियों का सुझाव दीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

India faces a paradox of food surplus and nutritional deficit. Analyse the structural reasons behind this paradox and suggest reform strategies. (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत में खाद्यान्न का दूसरा सबसे अधिक उत्पादन होता है। परन्तु कुपोषण से पीड़ित सर्वाधिक जनसंख्या रहती है।

खाद्यान्न उत्पादन 3?? मिलियन मीट्रिक टन जबकि वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 106th रैंक है।

कारण ⇒ – उत्पादन के पश्चात खाद्यान्न का नष्ट हो जाना
⇓
लगभग 8-12 %.

– भण्डारण क्षमता का अभाव
⇓
1?5 MMT की भण्डारण क्षमता जबकि 166 MMT का अभाव

– कच्चा भण्डारण ⇒ मिट्टी की कोठी
कवर एण्ड प्लिंथ

– क्षेत्रीय विषमता ⇒ उत्तराखंड में उत्पादन अधिक जबकि पूर्वी भारत में अभाव

VisionIAS

↳ सरकार द्वारा जनकल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार (PDS का 28% लीकेज)

↳ लोगों को खाद्य सुरक्षा, पोषण के बारे में जागरूकता का अभाव

↳ लैंगिक असमानता (50% + महिलाएं एनीमिया पीड़ित)
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 13वां

↳ पोष. खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कमी

सुझाव ⇒ (i) खाद्य उत्पादन में नवीन तकनीकों का प्रयोग
→ जैविक कृषि
→ कृषि जलवायु के अनुकूल

(2) फूड फोर्टिफिकेशन

(3) वैज्ञानिक भण्डारण क्षमता विकसित करना ⇒ (सहकारी भण्डारण परियोजना)

(4) FCI, CWC, SWC की भण्डारण क्षमता में वृद्धि।

(5) ग्रामीण स्तर पर भण्डारण को बढ़ावा देना।

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

PMGKY के तहत विश्व की सबसे बड़ी खाद्यान्न योजना।

(6) लोगों को पोषक तत्वों के बारे में जागरूकता.

(7) संचालित योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन.
जैसे
PDS _ ICDS, पोषण अभियान

(8) सेवोत्तम मॉडल, सिटीजन चार्टर ई गवर्नेंस का प्रयोग

(9) मोटे अनाज (सावां, कोदो, रागी) को बढ़ावा।

(10) NGO, सिविल सोसाइटी की भागीदारी, और विभिन्न हितधारकों के समन्वय से पोषण स्तर को सुनिश्चित कर SDG 2 व नीति निदेशक तत्वों (अनु० 47) को प्राप्त कर कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है

VisionIAS

19. श्रीलंका और मालदीव में आर्थिक संकटों के दौरान भारत द्वारा समय पर की गई कार्रवाई उसकी "नेबरहुड फर्स्ट" की नीति की सक्रियता को दर्शाती है। परीक्षण कीजिए कि भारतीय सहायता ने इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को कैसे प्रभावित किया है। हिंद महासागर क्षेत्र में सतत आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

India's timely response during the economic crises in Sri Lanka and the Maldives reflects its "Neighbourhood First" policy in action. Examine how Indian aid has impacted bilateral ties with these nations. What steps can further be taken to promote sustainable economic cooperation in the Indian Ocean region? (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत अपनी विदेश नीति के स्तर पर गुजराल डाक्ट्रिन, पंचशील, नेबरहुड फर्स्ट का प्रयोग करता है।

श्रीलंका में आर्थिक संकट के दौरान भारत की भूमिका

(1) मूलभूत सुविधाओं यथा खाद्यान्न दवाई की पहुँच सुनिश्चित करना।

(2) लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करना

(3) पेरिस क्लब के साथ ऋण समाधान समझौते के लिए बातचीत।

मालदीव → ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना
→ ऑपरेशन नीर, ऑपरेशन कैक्टस
→ उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक परियोजना
→ लाइन ऑफ क्रेडिट

VisionIAS

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

द्विपक्षीय संबंधों पर प्रभाव

(i) सॉफ्ट पावर का प्रतीक

(ii) पीपुल टु पीपुल कॉन्टैक्ट
मजबूत

(iii) लोगों में भारत के प्रति
सकारात्मक अभिवृत्ति,

(iv) संबंधों में सुधार.

(v) विदेश यात्रा को बढ़ावा (मालदीव
श्रीलंका बांग्लादेश से भारत आगमन

मालदीव में बढ़ रही राजनीतिक अस्थिरता

श्रीलंका — चीन का प्रभाव
Debt trap policy (हम्बनटोटा बंदरगाह)

सिंहली राष्ट्रवाद, तमिल — सुलह का मुद्दा

13th संविधान
संशोधन कानून

आगे का रास्ता ⇒ (i) पर्यटन को बढ़ावा देना

(ii) धार्मिक यात्रा — को बढ़ावा
(सिक्खों, चारधाम, बुद्धिस्ट पॉइंट)

(iii) IORA, IONS को बढ़ावा.

VisionIAS

(iv) ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा

(v) पश्चिमी अफ्रीका तक भागीदारी

(vi) कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को बढ़ावा।

(vii) IMEC को विकसित करना।

(viii) कोलम्बो सुरक्षा संवाद बिमस्टेक आसियान के साथ सहयोग बढ़ाना।

(ix) हिन्द महासागरीय देशों की सहायता।
उदा० ⇒ मालदीव ⇒ डॉर्नियर विमान
- ध्रुव हेली

(x) अनुसंधान, नवाचार क्षेत्रीय व अन्य वैश्विक संस्थाओं के साथ सहयोग कर क्षमता संवर्धन विकास।

अतः हिन्द महासागर वर्तमान की आर्थिक राजनीतिक, सामरिक व्यवस्था का आधार है भारत की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

VisionIAS

20. महाद्वीपीय संपर्क (कनेक्टिविटी) और मध्य एशिया तक पहुंच के संदर्भ में भारत के लिए अफगानिस्तान के भू-रणनीतिक महत्त्व पर चर्चा कीजिए। 2021 के बाद बदले राजनीतिक परिदृश्य ने भारत की कनेक्टिविटी और ऊर्जा गलियारे की महत्वाकांक्षाओं को किस प्रकार प्रभावित किया है? (उत्तर 250 शब्दों में दीजिए)

Discuss the geostrategic significance of Afghanistan for India in the context of continental connectivity and access to Central Asia. How has the altered political landscape post-2021 affected India's connectivity and energy corridor ambitions? (Answer in 250 words) 15

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

भारत अपनी वैश्विक स्थिति को सशक्त करने के लिए प्रयासरत है इसके लिए पूर्व में जहाँ एक्ट ईस्ट पालिसी वहीं मध्य में कनेक्ट सेन्ट्रल एशिया पालिसी का क्रियान्वयन कर रहा है

अफगानिस्तान के भू-रणनीतिक महत्व

- लैंडलॉक्ड
  - ऐतिहासिक रूप से भारत का सहयोगी (उदाहरण- ...)
- आर्थिक संसाधन तक पहुँच
  - कच्चा तेल प्राकृतिक
  - रेयर अर्थ एलिमेंट
- → बाजार
- → विदेश क्षेत्र
- → मध्य एशिया यूरोप तक पहुँचने की कुंजी
- बलूचिस्तान व कश्मीर भारत पर उपकार ...
- गोल्डन क्रिसेंट व आतंकवादी संगठनों को नियंत्रण
  - भारत की आन्तरिक व बाह्य सुरक्षा महत्वपूर्ण

VisionIAS

- चीन के प्रभाव को कम करने के लिए (BRI)
- अफगानिस्तान में भारत की परियोजना पीछे जाना के लिए
  - सलमा बांध

2021 के बाद बदलते परिदृश्य
- तालिबान का नियंत्रण
- अमेरिका की वापसी
- चीन का प्रभाव बढ़ना
- रूस यूक्रेन युद्ध
- आपूर्ति श्रृंखला बाधित होना
- अमेरिका-चीन ट्रेड वार

भारत के प्रयास
- कनेक्टिविटी
  - एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर
  - INSTC => इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर
- अश्गाबात समझौता

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

VisionIAS

उम्मीदवारों को इस हाशिए में नहीं लिखना चाहिए
Candidates must not write on this margin

— भारत ~~मध्य~~ मध्यपूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा

— IMT कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट

उर्जा पहल
- वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड
- ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस
- अन्तर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन

अतः भारत लगातार अपनी वैश्विक भूमिका को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है ताकि बहुध्रुवीय विश्व में अपनी स्थिति को सशक्त किया जा सके

VisionIAS

SPACE FOR ROUGH WORK

VisionIAS